INDIA'S BROADCAST SECTOR RECONFIGURES SATELLITE DEPENDENCIES

Regulatory tightening drives migration away from Chinese-linked satellite capacity, reshaping India's broadcast distribution landscape.

India's broadcast distribution ecosystem is undergoing a structural shift as operators move away from Chinese-linked satellite services following regulatory and national security directives. The transition reflects a broader policy push to reduce dependency on foreign infrastructure perceived as sensitive.

All major Indian broadcasters have begun migrating their operations to non-Chinese satellites after the government signalled restrictions on the continued use of services from providers such as Chinasat and Apstar. This development stems from a policy stance that discourages Chinese-linked entities from operating within India's satellite communication framework, particularly in sectors involving content distribution and national reach.

The move has, however, created short-term capacity constraints. AsiaSat, which has traditionally played a significant role in servicing Indian broadcasters, has been unable to fully bridge the gap. Regulatory complexities and approval processes through IN-SPACe have delayed fresh capacity allocations, even as existing authorisations face expiry timelines. While interim extensions have been granted in select cases, the lack of long-term clarity has forced broadcasters to accelerate contingency planning.

Industry stakeholders indicate that international satellite operators are now stepping in to address the emerging demand, though alignment with Indian regulatory frameworks remains a critical factor. The shift also underscores the growing importance of domestic satellite capabilities and policy-backed infrastructure development.

From a market perspective, the transition could lead to a rebalancing of satellite service providers in the region, with increased opportunities for non-Chinese global players and Indian operators. At the same time, broadcasters may face incremental costs and operational adjustments in the near term as they recalibrate distribution networks.

Overall, the development marks a significant inflection point in India's broadcast infrastructure strategy, where regulatory priorities, geopolitical considerations, and market dynamics are converging to redefine the satellite services landscape.■

सैटेलाइट पर अपनी निर्भरता को फिर से व्यवस्थित कर रहा भारत का प्रसारण क्षेत्र

नियामक सख्ती के चलते चीन से जुड़े सैटेलाइट क्षमता से दूर जाने का चलन बढ़ा है, जिससे भारत का प्रसारण वितरण परिदृश्य बदल रहा है।

भारत का प्रसारण वितरण इकोसिस्टम एक ढांचागत बदलाव से गुजर रहा है, क्योंकि ऑपरेटर रेगुलेटरी और राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देशों के बाद चीन से जुड़ी सैटेलाइट सेवाओं से दूर हट रहे हैं। यह बदलाव विदेशी संरचना पर निर्भरता कम करने की एक व्यापक नीति का हिस्सा है, जिसे संवेदनशील माना जाता है।

भारत के सभी प्रसारकों ने अपने संचालन को गैर-चीनी सैटेलाइट पर स्थानांतरिक करना शुरू कर दिया है। यह कदम सरकार के उस संकेत के बाद उठाया गया है जिसमें उसने चाइनासेट और ऐपस्टार जैसे प्रदायकों की सेवा के लगातार रोक लगाने की बात कही थी। यह बदलाव एक ऐसी नीतिगत सोच का नतीजा है जो चीनी कंपनियों को भारत के सैटेलाइट कम्युनिकेशन्स सिस्टम के अंदर काम करने से रोकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां कंटेंट वितरण और राष्ट्रीय पहुंच का मामला हो।

हालांकि, इस कदम से कम समय के लिए क्षमता की कमी पैदा हो गयी है। एशियासेट, जिसने पारंपरिक रूप से भारतीय प्रसारकों को सेवा देने में अहम भूमिका निभायी है, इस कमी को पूरी तरह से भर नहीं पाया है। इन-स्पेस के जरिए रेगुलेटरी पेचीदगियों और मंजूरी की प्रक्रियाओं ने नयी क्षमता के आवंटन में देरी की है, जबकि मौजूदा मंजूरियों की समय सीमा खत्म होने वाली है। हालांकि कुछ मामलों में अंतरिम विस्तार दिया गया है, लेकिन लंबे समय के लिए स्पष्टता की कमी ने प्रसारकों को आपातकालीन योजना बनाने में तेजी लाने पर मजबूर कर दिया है।

उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट ऑपरेटर अब बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आगे आ रहे है। हालांकि भारतीय रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ तलमेल बिठाना अभी भी एक अहम पहलू बना हुआ है। यह बदलाव घरेलू सैटेलाइट क्षमताओं और नीति समर्थित संरचना विकास के बढ़ते महत्व को दिखाता है।

बाजार के नजरिए से देखें, तो इस बदलाव से इस क्षेत्र में सैटेलाइट सेवा देने वालों के बीच संतुलन फिर से बन सकता है, जिससे चीन के अलावा दूसरे देशों के ग्लोबल खिलाड़ियों और भारतीय ऑपरेटरों के लिए ज्यादा मौके खुलेंगे। साथ ही प्रसारकों को भी कम समय के लिए कुछ ज्यादा खर्च और कामकाज में कुछ बदलावों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वे अपने वितरण नेटवर्क को फिर से व्यवस्थित करेंगे।

कुल मिलाकर, यह घटनाक्रम भारत की प्रसारण इंफ्रास्ट्रक्चर रणनीति में महत्वपूर्ण नोड़ है, जहां विनियामक प्राथमिकतायें, भू-राजनीतिक विचार और बाजार की गतिशीलतायें मिलकर सैटेलाइट सेवाओं के परिदृश्य को फिर से परिभाषित कर रही है। ■